## दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

# एक बजट को पलटते जाना

किसी भी वित्तमंत्री के लिए बजट का दिन उसके जन्मदिन से कहीं ज्यादा बड़ा और अहमियत वाला होता है। देश के लिए बजट बनाना एक यादगार और मील का पत्थर जैसा काम होता है। समय के साथ बजट के कुछ प्रस्तावों में संशोधन भी होंगे, आलोचना होने पर एक दो प्रस्ताव वापस भी लिए जा सकते हैं। कुछ अव्यावहारिक, अतार्किक प्रस्तावों को बिना किसी कार्रवाई के खत्म होने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

### बनाना और मिटाना

हालांकि 2019-20 का बजट अपने में अद्वितीय है। मुझे हाल में कोई ऐसा बजट याद नहीं आता, जब किसी वित्तमंत्री ने बजट तैयार करने के बाद पूरे होशो-हवास में उसे पलट दिया हो। बजट भाषण के दौरान प्रमुखता से रखे गए प्रस्तावों की मैंने एक सूची बनाई है। बजट बाद चर्चा में इन प्रस्तावों की खूबियों का एलान किया गया था। इनमें से हर एक को पलट दिया गया या वापस ले लिया गया। 1 फरवरी, 2019 से 23 सितंबर, 2019 के बीच 2019-20 का बजट संदिग्ध खातों के व्यर्थ विवरण की तरह सिमट कर रह गया।

उन बजट प्रस्तावों की सूची जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया

| क्रम सं. | जुलाई, 2019 के बजट में प्रस्ताव | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | एफपीआइ और घरेलू निवेशकों पर यह प्रस्ताव 23 अगस्त को लंबी और कम अवधि वाले कैपिटल वापस ले लिया गया। गेन पर सरचार्ज। | यह प्रस्ताव 23 अगस्त को वापस ले लिया गया।<br>'पूंजी बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी शेयरों / यूनिटों, जो धारा 111 ए और 112 ए में निर्दिष्ट हैं, के हस्तातंरण से होने वाले लंबी और छोटी अवधि के पूंजीगत लाभ पर वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2019 के जरिए लगाए गए अधिभार की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया गया है।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त, 2019 को संवाददाता सम्मेलन में। |
| 2 | ओवरसीज सॉवरेन बांड जारी करना। | कोई फैसला नहीं, लेकिन इसे लगभग छोड़ ही दिया है<br>'किसी भी बाजार में जाने से पहले उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक सुधार करने और विचार-विमर्श करने की जरूरत है। इसके लिए उचित तरीका निकालने के लिए अभी काम चल रहा है और इसकी खूबियों-खामियों की जांच की जा रही है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और यह जारी रहेगी। इस साल के लिए मौजूदा सारी उधारियां रुपए के गुणक में बांड में हैं।' - सचिव, आर्थिक मामले, अतनु चक्रवर्ती, 23 सितंबर 2019 |
| 3 | 'जहां तक कारपोरेट कर का सवाल है, हम इसकी दरों में चरणों में इसमें कमी जारी रखेंगे। इस वक्त पच्चीस फीसद की निम्न दर उन कंपनियों पर लागू होगी, जिनका कारोबार ढाई सौ करोड़ रुपए सालाना तक है। मैं इस दायरे को बढ़ा कर उन कंपनियों को भी इसमें शामिल करती हूं, जिनका सालाना कारोबार चार सौ करोड़ रुपए है। इसमें 99.3 फीसद कंपनियां आ जाएंगी। इस कर दर से अब सिर्फ 0.7 फीसद कंपनियां ही बाहर रह जाएंगी।' - पैरा 110 , बजट भाषण, 5 जुलाई, 2019<br>कारपोरेट कर में कटौती | 23 सितंबर, 2019 को अध्यादेश के जरिए इसे बदल दिया गया<br>सारी घरेलू कंपनियों को 22 फीसद की दर से कारपोरेट कर देना होगा (सेस और सरचार्ज मिला कर यह प्रभावी दर 25.17 फीसद बैठती है।) इसके लिए इन कंपनियों के साथ शर्त यह है कि उन्हें अब और कोई कर रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इन कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) भी नहीं लगेगा। कोई भी नई घरेलू कंपनी जो एक अक्तूबर, 2019 के बाद बनाई गई है, उसे पंद्रह फीसद की दर से कारपोरेट कर देना पड़ेगा, जो प्रभावी रूप से 17.01 फीसद बैठेगा। - 23 सितंबर , 2019 |
| 4 | एंजेल टैक्स | 23 अगस्त, 2019 को वापस ले लिया गया<br>'इसमें वाणिज्य मंत्रालय के तहत पंजीकृत स्टार्टप पर आयकर कानून की धारा 56 (2)(सात बी) लागू नहीं होगी।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में। |
| 5 | कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर के उल्लंघन का अपराधिकरण (31 जुलाई, 2019 को कंपनी कानून 2013 में संशोधन द्वारा) | 23 अगस्त, 2019 को वापस ले लिया गया<br>'वह हर संदेह, जो बाहर बना हुआ था, उसे मैं आज दूर कर देना चाहूंगी। मुकदमे के रास्ते पर चलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी को नागरिक मामलों की तरह ही लिया जाएगा, न कि आपराधिक मामलों की तरह।' - निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में। |
| 6 | नई इंटरनल कंबंशन इंजन (आइसीई) वाली कारों के लिए पंजीकरण शुल्क छह सौ रुपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए किया जाता है। आइसीई कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क पंद्रह हजार रुपए प्रस्तावित किया जाता है (26 जुलाई, 2019 को प्रस्तावित) | 23 अगस्त 2019 को वापस ले लिया गया<br>नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 2020 तक टाल दिया गया है- निर्मला सीतारमण, 23 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन में। |

### परेशानियों का पुलिंदा

दुर्भाग्य से, वित्तमंत्री ने बजट में जो लुभावनी घोषणाएं की थीं, उन्हें वापस लेने भर से उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ज्यादातर ढांचागत और कुछ चक्रीय समस्याएं भी अर्थव्यवस्था की तबाही का कारण बनी हैं, अर्थव्यवस्था डूब गई, आंकड़े बुरी तरह गड़बड़ा गए, बड़ी-बड़ी डींगें भी ज्यादा राजस्व नहीं जुटा पाईं या खर्च को काबू में रख पाईं, और इनका नतीजा महालेखाकार नियंत्रक के यहां से हर महीने जारी होने आंकड़ों में स्पष्ट नजर आया है।

आखिरी बार अक्तूबर 2019 में ये आंकड़े आए थे, जो बता रहे हैं कि शुद्ध राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान के मुकाबले मुश्किल से 41.4 फीसद भी नही रही, कुल प्राप्तियां 44.9 फीसद रहीं, वित्तीय घाटा 102.4 फीसद रहा और राजस्व घाटा 112.5 फीसद। वित्त मंत्री के पास अब और खर्चा करने या उधार लेने का कोई रास्ता नही बचा है।

### धन डालने का भ्रम

फिर भी 5 जुलाई, 2019 से, वित्तमंत्री ने भारी-भरकम रकम देने का एलान किया है, जो कई क्षेत्रों में डाली जाएगी, जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (सत्तर हजार करोड़), रियल एस्टेट (पच्चीस हजार करोड़), एनबीएफसी और एचएफसी (बीस हजार करोड़), आइडीबीआइ बैंक (चार हजार पांच सौ सत्तावन करोड़ रुपए) और पंजाब नेशनल बैंक (सोलह हजार करोड़ रुपए)।

जैसा कि डा. अरविंद सुब्रमण्यन और जोश फेलमेन का आकलन है कि अर्थव्यवस्था आइसीयू की ओर जाती दिख रही है, वित्तमंत्री को सिर्फ हरा ही हरा नजर आ रहा है!

# जय और पराजय

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

जय में भी पराजय हो सकती है।

इस बात पर चर्चा करना व्यर्थ है कि हम अल्पकालिक जय की या फिर दीर्घकालिक जय की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पल में ही अगला पल छिपा होता है। दूसरे शब्दों में, इस पल की जय के द्वारा ही दूसरे पल की जय तक पहुंचा जा सकता है। यह बात पराजय पर भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में हार का मुंह देखता है, तो उसमें साहस का ह्रास हो जाता है और वह अपने आप को उस तरह नहीं संभाल पाता है कि तुरंत वह अपनी पराजय को जय में बदल सके। हां, कुछ बिरले होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, पर अमूमन ऐसा साधारण रूप में नहीं होता है। हारे हुए व्यक्ति को अपने को तब्दील करने में बहुत वक्त लगता है। अक्सर एक पूरी उम्र ही लग जाती है।

> बेहद अहमक किस्म के लोग दुस्साहस की वजह से अपने को 'लाइम लाइट' में लाने में कामयाब हो जाते हैं। वे दुस्साहस को अपनी योग्यता मान लेते हैं, क्योंकि वे वास्तविक सारगर्भी योग्यता से अनभिज्ञ होते हैं। वे योग्यता के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुस्साहस के जरिए जय हासिल करना उनको प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। उनके लिए दुस्साहस समझ से ज्यादा अहमियत रखता है।

पर ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा जीतता ही रहे। उसको भी परिस्थितियां या फिर अति-आत्मविश्वास कभी न कभी हार के द्वार पर ला खड़ा करता है, पर चूंकि उसके पीछे जीत की एक छोटी-मोटी शृंखला होती है, तो उसके लिए अपने को विजय पथ पर पुनः लौटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। संघर्ष तो करना पड़ता है, पर उसका संघर्ष हारे हुए आदमी की जद्दोजहद से बहुत कम होता है। आधा मसला तो उसके आत्मविश्वास से ही हल हो जाता है और बाकी रणनीति पर पुनः विचार कर के।

वैसे दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं। पर दोनों के लिए एक ही चीज पर सारा दारोमदार है। आत्मविश्वास का होना या न होना लक्षित करता है कि व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। अक्सर बेहद काबिल लोग भी अंधेरे बंद कोनों में दुबके रह जाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश में आने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। दूसरी तरफ बेहद अहमक किस्म के लोग दुस्साहस की वजह से अपने को लाइम लाइट में लाने में कामयाब हो जाते हैं। वे दुस्साहस को अपनी योग्यता मान लेते हैं, क्योंकि वे नेतृत्व की वास्तविक सारगर्भी योग्यता से अनभिज्ञ होते हैं। वे योग्यता के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुस्साहस के जरिए जय हासिल करना उनको प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। उनके लिए दुस्साहस समझ से ज्यादा अहमियत रखता है। इस प्रवृत्ति के चलते वे समझना नहीं चाहते, विश्लेषण नहीं करना चाहते। वे बस करना चाहते हैं- और वही करना चाहते हैं जो मौजूदा पल में उन्हें जय का अहसास दिला सके। उनकी आत्म संतुष्टि जीत की क्षणिक अनुभूति में है।

निजी जीवन में जय और पराजय का प्रभाव व्यक्ति या उसके बेहद करीबी माहौल तक ही सीमित रहता है। इस घेरे में भी ऐसा हो सकता है कि एक अयोग्य सदस्य अपने दुस्साहस में कुछ ऐसा कर जाए, जिसका प्रभाव सारे कुटुंब पर लंबे अरसे तक पड़े। इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजपरिवार हैं, जिनके किसी एक पूर्वज ने ऐसा कुछ दुस्साहस किया, जिससे सदियों तक सत्ता और उसकी ताकत का प्रभाव उसके वंशजों को विरासत में मिला था। इसी इतिहास में ऐसे भी राजपरिवार हैं, जिनकी बनी-बनाई प्रतिष्ठा एक क्षण में मिट्टी में मिल गई और अगली पीढ़ियां वक्त के अंधेरो में गुम हो गई हैं।

साहस और दुस्साहस में राई भर का फर्क है। विजेता साहसी बताया जाता है और पराजित को दुस्साहसी कहा जाता है। पर जब पांसा फेंकने का क्षण होता है, तो वह किस पाले में पड़ेगा इसकी संभावना बराबर ही होती है। महाराणा प्रताप ने कई पराजय देखी थी, पर उनको हमेशा साहसी कहा जाता है। दूसरी तरफ, डकैत को हमेशा दुस्साहसी ही कहा जाएगा। एक तरह से जोखिम दोनों ही कामों में है- युद्ध में भी और डकैती में भी। दोनों के परिणाम कर्ता के लिए गंभीर हो सकते हैं। पर फर्क केवल इतना है कि वीर राणा प्रताप संप्रभुता के लिए युद्ध में उतरे थे, जबकि डकैत ने जोखिम अपनी धन लोलुता के कारण उठाया था। उसका कर्म हमेशा दुस्साहस की श्रेणी में आएगा और समाज से उसको कभी स्वीकृति नहीं मिलेगी। डकैत अपने अंचल में लोकप्रिय भी हो सकता है, शक्तिशाली भी, अपराजित भी, पर प्रसिद्ध कभी नहीं होगा। उसको मशहूर के बजाय कुख्यात ही कहा जाएगा।

समझदार और योग्य लोग इस फर्क को कायम रखने में सक्षम होते हैं। औरों के लिए क्षण की जीत या हार ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। वे सिर्फ अपनी नाक तक ही देख पाते हैं। उसके आगे उनके लिए सब धुंधला है और इसलिए बेमानी भी है। पीछे भी जो कुछ बीत चुका है उनके लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उनकी आगे और पीछे दोनों की दृष्टि बाधित है। वे जो करेंगे दुस्साहस में करेंगे, जिसका प्रतिउत्तर किसी और के दुस्साहस में निहित होगा।

# इस भ्रम के माहौल में

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

बहुत बार कह चुके हैं गृहमंत्री कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है नए नागरिकता कानून में। बहुत बार कह चुके हैं कि जब देश भर में भारत के नागरिकों की नागरिकता दर्ज की जाएगी एनआरसी में, तो किसी असली भारतीय को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन शायद अपने ही पुराने भाषण भूल कर कह रहे हैं ये बातें अब, जब देश के शहरों और विश्वविद्यालयों में उनके नए नागरिकता कानून का इतना विरोध दिखने लगा है। भूल गए हैं कि मुसलमान 'घुसपैठियों' को उन्होंने दीमक कहा है बार-बार। भूल गए हैं कि उन्होंने बहुत बार कहा है कि उनको ''चून-चून' कर बाहर फेंकेंगे।''

किस मकसद से उन्होंने ये तकरीरें दीं, सिर्फ गृहमंत्री खुद जानते हैं, लेकिन आम मुसलमान तक संदेश यही पहुंचा है नागरिकता कानून में संशोधन के बाद कि उनके खिलाफ साजिश है यह कानून। क्यों नहीं यह संदेश जाएगा, जब गृहमंत्री इतनी बार कह चुके हैं कि सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए यह संशोधन किया गया है। बाकी रहते हैं सिर्फ मुसलमान, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में उत्पीड़ित शिया और अहमदीया भी हैं। सो, अगर खौफ का माहौल बन गया है भारत के मुसलमानों में, तो क्यों न बने? अशांति और अराजकता देश के बड़े शहरों में फैलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक चुनावी भाषण में पिछले हफ्ते कांग्रस पार्टी को चुनौती दी यह कहते हुए कि क्या कांग्रेस हर पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता देना चाहती है, क्या तीन तलाक को वापस लाना चाहती है, क्या अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहती है?

चुनौती देते हुए मोदी ने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये तमाम कदम मुसलमानों से वास्ता रखते हैं। थोड़ा सोचने के बाद दिया होता यह भाषण तो जरूर दिखता उन्हें कि अशांति के माहौल में ऐसा भाषण आग सुलगाने का काम करेगा, बुझाने का नहीं। सो, सुलगती रही है आग और लखनऊ में जहां हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी तक जला डाली और मीडिया के ओबी वाहन भी जलाए गए, मालूम पड़ा है बाद में कि नकाबपोश बदमाश घुस गए थे विरोध करते लोगों के बीच और हिंसा करने के बाद गायब हो गए। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन विरोध की बुनियाद असली है, सो सबको 'अर्बन नक्सल' और राष्ट्रद्रोही कहने से आग और भड़कने वाली है।

अमन-शांति लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो जरूरी है कि अपनी ऊंचाइयों से उतर कर उन छात्रों से बातचीत शुरू करने का प्रयास करें, जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। जरूरी है इस बात पर भी ध्यान देना कि दुनिया में उनकी छवि कितनी बदल गई है उनके दूसरे दौर के पहले महीनों में। अपने पहले दौर में जब उन्होंने विकास और परिवर्तन के नारे पर पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो दुनिया उनको भारत की नई आशा का प्रतीक मानती थी। जब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है भारत में, जो निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाएगा लाल फीताशाही हटा कर, तो विदेशी निवेशकों की कतारें लग गई थीं।

> अमन-शांति लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो जरूरी है कि अपनी ऊंचाइयों से उतर कर उन छात्रों से बातचीत शुरू करने का प्रयास करें, जिन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया है।

अफसोस कि अपने दूसरे दौर में उन्होंने विकास और परिवर्तन को ताक पर रख कर उन मुद्दों पर ध्यान दिया है, जो आरएसएस को प्रिय हैं। कोई छिपी बात नहीं है कि आम संघी मुसलमानों की तरफ शक की नजरों से देखता है, उनके राष्ट्र प्रेम और उनके मजहब पर शक करता है। सो, जब कोई सरकार ऐसे कदम उठाती है जो मुसलमानों के खिलाफ दिखने वाले होते हैं, तो आरएसएस के बड़े नेता हमेशा अपनी खुशी जाहिर करने में देर नहीं करते हैं। मोदी के दूसरे दौर में सिर्फ ऐसे कदम ही उठे हैं। कश्मीर जो भारत का अकेला मुसलिम बहुल राज्य था, तीन टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। और अब आया है ऐसा नागरिकता कानून, जिसने आम मुसलमानों में एनआरसी की संभावना से ही डरा दिया है।

मोदी अपने आप को गांधीजी का भक्त मानते हैं, सो विनम्रता से अर्ज करना चाहती हूं कि वे अपने आप से पूछें कि गांधी आज हमारे बीच होते, तो क्या सरकार के इस नागरिकता कानून के समर्थन में खड़े होते या इस कानून के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बीच दिखते? इस सवाल का जवाब उनको फौरन मिल जाना चाहिए, इसलिए कि हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारा लाने के प्रयास में ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। इस भाईचारे को कायम करना मोदी सरकार का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए अब। इसलिए कि इस नए नागरिकता कानून ने अगर मुसलमानों को एक संदेश दिया है, तो हिंदुओं को एक अलग और उतना ही खतरनाक संदेश दिया है कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है।

सोशल मीडिया पर जो लोग अपने आप को मोदी के कट्टर भक्त मानते हैं, अभी से कहने लगे हैं कि समय आ गया है, मुसलमानों को भारत से भगा देने का। ताने देते हुए ट्वीट करते हैं कि मुसलमानों के लिए कई इस्लामी मुल्क हैं जाने को और पाकिस्तान तो है ही पड़ोस में। ऐसी बातें करते हुए शायद जानते नहीं हैं कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों का शुरू से सपना रहा है कि भारत एक बार फिर टूट जाएगा और बंटवारा होगा फिर से इस्लाम के नाम पर। इस बुरे सपने को पूरा करने का काम कर रहा है यह नया नागरिकता कानून, क्योंकि आम मुसलमानों ने इसको जोड़ लिया है एनआरसी के साथ, जिसमें वे जानते हैं कि लाखों, करोड़ों गरीब मुसलमान साबित नहीं कर पाएंगे कि वे हमेशा से रहे हैं भारत के नागरिक। जिनके सिर पर छत ही नहीं है, कहां से लाएंगे सबूत के दस्तावेज? कैसे साबित कर पाएंगे अपनी नागरिकता?

# एक गुस्सा बिखरता हुआ

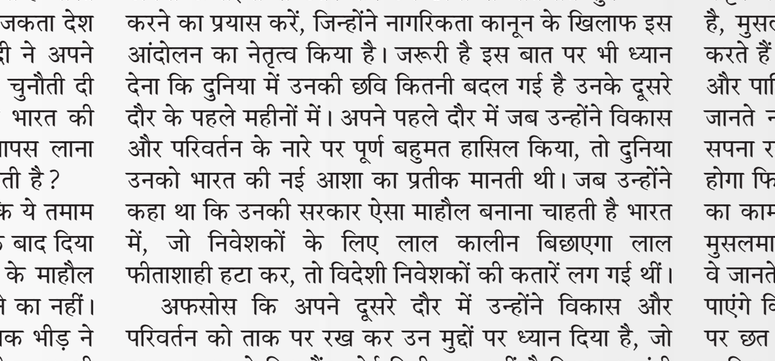

बाख़बर

■ सुधीश पचौरी

दिल्ली, अमदाबाद, मुंबई, बंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी आदि दो दर्जन शहरों में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हैं। खबरें टपकती हैं : कुल सात राज्यों में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन है। नहीं, ये अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन हैं। असम में दो मरे। यूपी के दो दर्जन शहरों में विरोध प्रदर्शन! पुलिस चौकी भस्म! छह मरे!

फिर जामिया में विरोध। फिर जंतर मंतर और सीलमपुर में विरोध! पचासी गिरफ्तार। ओवैसी उवाच : हमें सड़कों पर निकलना होगा...

जामिया में बसों का दहन। 'आप' बरक्स 'भाजपा' बरक्स 'कांग्रेस' के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप। दो-तीन वीडियो प्रसारित कि किसने कब कहां हिंसा की? कब आग लगाई? कब कैसे लाइब्रेरी में पुलिस घुसी? कैसे मारा-पीटा? एक युवक की जांघ में गोली लगी। एक को सीने में लगी। प्रदर्शन के नए हीरो, नई हीराइनें।

एक अंग्रेजी चैनल पर एक पैनलिस्ट इसे 'नाजी इंडिया' बताता है और 'कंसंट्रेशन कैंप' बनने की आशंका जताता है। एक बेहद तुनकमिजाज पैनलिस्ट दूसरे की टिप्पणी से नाराज होकर बहस से उठ कर चली जाती है। एक अन्य अंग्रेजी चैनल पर एक पैनलिस्ट जामिया और जेएनयू को बंद करने की सलाह देता है।

शनिवार की सुबह एक युवक बिना कमीज के नंगे बदन जामिया के एक गेट पर बैठ जाता है, जिसकी खबर सबसे पहले एक हिंदी चैनल को मिली दिखती है। उसी की एक रिपोर्टर उसकी मम्मी बन कर हर तीसरे वाक्य में अपना वात्सल्य टपकाती, उसे मनाती रहती है कि इतनी ठंड है और आपने कुछ नहीं पहना है, आपको ठंड लग जाएगी। आप कपड़े पहन लीजिए। वह दो घंटे तक मम्मी बन उसकी मान-मनौवल करती रहती है। कैमरा देख सीन बनाने के लिए लोग जुट जाते हैं। कुछ युवा की पीठ सहलाने लगते हैं। रिपोर्टर कहती रहती है कि मैं आपकी ही बात लोगों तक पहुंचाऊंगी, आप कपड़े पहन लीजिए...

यह कौन-सी पत्राकारिता है? ऐसे में प्रदर्शनकारियों का दिमाग न खराब न हो तो क्या हो? इस 'हाइप' को देख और कई युवा नंगे बदन आकर बैठ जाते हैं। जामिया में फिर जमावड़ा होने लगता है।

एक चैनल पर एक दल के नेता इसे 'सिविल वार की-सी स्थिति' कहते हैं। निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाते हैं। इलाहाबाद, हैदराबाद, वाराणसी, नदवा, लखनऊ से विरोध प्रदर्शनों की लाइव खबरें आने लगती हैं। सभी जामिया में छात्रों पर हुए पुलिस अत्याचार के विरोध में निकल पड़ते हैं। वाराणसी से लेकर मद्रास आइआइटी के छात्र जामिया में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निकल पड़ते हैं। बंगलुरू में रामचंद्र गुहा गिरफ्तार किए जाते हैं और शाम तक चैनलों पर 'आपबीती' सुनाने आ बैठते हैं।

एक चैनल खबर देता है कि जामिया की हिंसा के पीछे बाहरी तत्व रहे। फिर लाइन आती है कि राजनीतिक दल रहे! कोलकाता में ममता एनआरसी-सीएए विरोधी रैली का नेतृत्व करती हैं। विपक्षी नेता कहते हैं कि हम दमन को कंडेम करते हैं, यह कानून संविधान विरोधी है। प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठ जाती हैं, फिर जल्दी ही उठ जाती हैं।

एक चैनल पर एक पैनलिस्ट कई बार कहता है कि सीएए-एनआरसी को लेकर उठती आशंकाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई मुद्दों पर कन्फ्यूजन है। लेकिन प्रवक्ता कहते रहते हैं कि यह सब न्यस्त स्वार्थों की कारस्तानी है। गृहमंत्री दो चैनलों पर बातचीत करते बार-बार साफ करते हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक को इससे कोई खतरा नहीं है। यह तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है।...

लेकिन इतने भर से लोगों को भरोसा नहीं होता। पूछने पर कई प्रदर्शनकारी कहते हैं, कहने से क्या? वे लिख कर दें, छाप कर दें।... सीलमपुर का एक लड़का कहता है : एक बेटे को यतीम कर दिया और एक को गोद ले लिया, ये कौन-सा इंसाफ है?

बहुत से भ्रम, डर, शक, आशंकाएं और वहम एक साथ जग गए हैं और कोई नहीं है, जो उनको प्यार से समझाए। इनको उनसे डर है, तो उनको इनसे डर है। चैनल बहुतों से बात करते हैं और वे सभी समान रूप से कहते हैं कि वे मुसलमान हैं। पिछले बरसों से वे निशाने पर हैं। वे कहां जाएं? ऐसे प्रदर्शनकारियों की आशंकाएं बढ़ती हैं और कैमरों के जरिए अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं। वृहस्पतिवार को बाईस शहरों में विरोध प्रदर्शन नजर आते हैं।

> बहुत से भ्रम, डर, शक, आशंकाएं और वहम एक साथ जग गए हैं और कोई नहीं है, जो उनको प्यार से समझाए। इनको उनसे डर है, तो उनको इनसे डर है।

ममता कहती हैं, मेरे जीते-जी सीएए लागू नहीं हो सकता। संसद में इसका समर्थन करने के बावजूद नवीन पटनायक भी कह उठते हैं कि यह स्वीकार्य नहीं।

झारखंड की एक सभा में पीएम कहते हैं कि भारत के नागरिक चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सिख या ईसाई, किसी पर यह कानून लागू नहीं होगा।... एक चैनल पर बड़े वकील हरीश साल्वे समझाते हैं कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और राज्य सरकारें लागू करने से मना नहीं कर सकतीं।...

एक अंग्रेजी चैनल लाइन लगाता है : यह 'धरना' नहीं 'दंगा' है। दूसरा लाइन लगाता है : यह 'प्रोटेस्ट' नहीं 'दंगा' है। क्या 'सूडोज' चाहते हैं कि दिल्ली जले? ऐसे चैनल आंदोलित लोगों को 'सूडोज' कह कर सिर्फ चिढ़ाते हैं और जाने-अनजाने तीखी प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। ध्यान रहे, आम जनता आपकी खबरों से अपना नजरिया बनाती है और प्रतिक्रिया भी करती है। एक विश्लेषक अवश्य कहता है कि यह बहुत से कारणों से बना संचित गुस्सा है, जो बिखर कर निकल रहा है।

वृहस्पतिवार की रात को ही शुक्रवार के प्रदर्शनों के संकेत मिलने लगते हैं। कैमरे सुबह से ही दिल्ली जामा मस्जिद पर जम जाते हैं। नमाज के बाद अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीमसेना के चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं और फिर पुलिस की पकड़ से गायब हो जाते हैं। शाम को जामा मस्जिद से निकल कर लोग दिल्ली गेट पर नारे लगाने लगते हैं। दिल्ली गेट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। पौने छह बजे आंदोलन खत्म होता है।

सात दिन बाद गृहमंत्रालय की मार्फत एक आश्वासन दिखता है कि अभी सीएए के नियम नहीं बने। लोग चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं!

नई दिल्ली

www.readwhere.com